



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 24 जनवरी, 2005/4 माघ, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जनवरी, 2005

संख्या एल० एल० आर० डी० (6)-26/2004-लेज. — हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 23-1-2005 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश नगर

नियम (संशोधन) विधेयक, 2004 (2004 का विधेयक संख्यांक 22) को वर्ष 2005 के अधिनियम संख्यांक 4 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2004

(मा० राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 23-1-2005 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 12) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2004 है।

संक्षिप्त
नाम और
प्रारम्भ।

(2) यह 26 अक्तूबर, 2004 को प्रवृत्त होगा और सदैव प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

1994 का
12

2. हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 264 में खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड (घ) जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

धारा 264
का
संशोधन।

“(घ) कूड़े-कचरे का, आयुक्त द्वारा विहित रीति में नगर निगम द्वारा आगामी निपटान हेतु, ऐसे निपटान के लिए फीस के संदाय पर, जो सरकार द्वारा विहित की जाए, संग्रहण और निक्षेप करें।”

3. मूल अधिनियम की धारा 269 में, उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित नई उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

धारा 269
का
संशोधन।

“(3) उप-धारा (1) में अन्तर्निष्ठ किसी बात के होते हुए भी, गृह स्वामी या किसी परिसर के अधिभोगी का यह कर्तव्य होगा कि वह, यथास्थिति, अपने शौचालयों, मूत्रालयों और मलाशय (सेप्टिक टैंक) को, निगम से सीवरेज कनेक्शन प्राप्त करके, अपने खर्चे पर निगम की सीवरेज लाइन से जोड़ेगा और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो वह, ऐसे कनेक्शन के लिए अन्य प्रभारों के अतिरिक्त, जुर्माने से दण्डनीय होगा जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा परन्तु पांच सौ रुपये से कम नहीं होगा :

परन्तु यह कि जहां सीवरेज लाइन किसी अन्य व्यक्ति की भूमि में से जा रही है तो वहां पर ऐसी भूमि की सीमा रेखाओं में से सीवरेज कनेक्शन को सीवरेज लाइन से जोड़ा जाएगा या जहां भवन का निर्माण हो गया है वहां पर लाइन ऐसे भवन के सैंटबैक्स में से ले जाई जाएगी, जो भी साध्य हो।”

धारा 302
का
संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 302 की उप-धारा (1) में निम्नलिखित नए शब्द जोड़े जाएंगे, अर्थात्:—

“(क) किसी भी सार्वजनिक स्थान में बन्दरों, लंगूरों और अन्य आकारा जानवरों को नहीं खिलाएगा; या

(द) सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक सड़क, सार्वजनिक गली या दीवारों पर नहीं थकेगा; या

(ठ) किसी प्रकार के कूड़े-कचरे/कूड़े-करकट आदि को इस प्रयोजन के लिए निगम द्वारा उपलब्ध करवाए गए कंटेनर के सिवाय किसी सार्वजनिक स्थान, सड़क, गली या खुले पहाड़ी पार्श्व में नहीं फेंकेगा ।

स्पष्टीकरण.—खण्ड (ज) के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति “सार्वजनिक स्थान” के अन्तर्गत मन्दिर नहीं होगा।”।

2004 के
अध्यादेश
संख्यांक 3
का निरसन
और
व्यावृत्तियाँ ।

5. (1) हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2004 का एतद्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 4 of 2005.

**THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION
(AMENDMENT) ACT, 2004**

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 23RD JANUARY, 2005)

AN

ACT

*further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994
(12 of 1994).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-fifth Year of the Republic of India, as follows :

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2004.

Short title
and comm-
encement.

(2) It shall and shall always be deemed to have come into force on the 26th day of October, 2004.

12 of 1994

2. In section 264 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (hereinafter referred to as the "principal Act"), after clause (c), the following new clause (d) shall be added, namely :—

Amendment
of section
264.

“(d) to collect and deposit the garbage for further disposal by the Municipal Corporation in the manner prescribed by the Commissioner, on payment of fee for such disposal as may be fixed by the Government.”.

3. In section 269 of the principal Act, after sub-section (2), the following new sub-section shall be added, namely :—

Amendmen
of section
269.

“(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), it shall be the duty of the houseowner or occupant of any premises to connect his latrines, urinals and septic tank, as the case may be, with sewerage line of the Corporation at his own expenses by getting sewerage connection from the Corporation, and if he fails to do so, he shall be punishable with a fine which may extend to two thousand rupees but shall not be less than five hundred rupees, in addition to other charges for such connection :

Provided that where sewerage line is passing through other person's land, the sewerage connection shall be connected to the sewerage line through the boundary lines of such land or where the building has been constructed, the line shall be laid through the setbacks of such building, whichever is feasible.”.

Amendment
of section
302.

4. In section 302 of the principal Act, in sub-section (1), the following new clauses shall be added, namely :—

- “(j) feed monkeys, langoors and other stray animals in any public place ; or
- (k) spit on public place, public road, public street or walls; or
- (l) throw any type of garbage/refuse etc. on any public place, road, street or in open hillside except in a container provided by the Corporation for this purpose.

Explanation.—For the purpose of clause (j), the expression “public place” shall not include temple.”.

Repeal of
Ordinance
No. 3 of
2004.

5. (1) The Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2004 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.